SHRIMATI KAMLA S1NHA: My question was very specific, whether the Central Government plans to bring out a Central legislation to be called Employment Guarantee Act, and not the employment guarantee scheme on Maharashtra pattern.

SHRI P. A. SANGMA: No, Madam.

SHRI JAGESH DESA1: Just now the Minister said that it is not possible to have employment insurance because of the problem of resources. I have visited so many public sector undertakings. They have vast chunks of Jand for development but there land's, are not being mad© use of. I want to know whether the Government would consider to allow sale of those lands which are in urban areas. The prices of these lands have gone up to such an extent that I think with these resources we will be able to give them finance for purposes of modernisation. If that is done, I feel that there will not be any problem of closure and sufficient employment can be generated. I want to know whether the Government will consider it. The Execiir fives Association of IISCO yesterday said that the worth of assets is only Rs. 380 crores. But that is their estimate; they may be wrong. But the present value of assets is Rs. 16,000 crores. I want to know whether the Government will conduct a survey of such industries and wherever excess land is there and you can get a good rice by selling that land, whether the Government will conn sider my suggestion to mobilise resour ces.

SHRI P. A. SANGMA: These lands. are governed by the State legislations like Urban Ceiling Act, Municipality Act, Corporation Act. Practically we do not have power over this. Normally the State Governments do not give permission to dispose of those lands. I quite agree that this could be one way of mobilising resources for the public sector or for any other purpose that Government may think. This has been taken up by the Ministry of Urban Development and Department of Public Sector Enterprises with the respective State Governments.

THE DEPUTY CHAIRMAN; Next question.

Foreign Secretary level talks between India and Pakistan

*422. SHRI ANANT RAM JAIS-WAL:f DR. ABRAR AHMED:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Foreign Secretary-level talks between India and Pakistan are to be held at New Delhi in the middle of August, 1992 and the date of the meeting was finalised by the Prime Minister when he met Pakistani Prime Minister in Rio de Janeiro last month;

(b) whether Government propose to raise the issues of growing militant activities in Jammu and Kashmir and supply of arms to the militants during the talks;

(c) whether Government would also discuss ban on production, stockpiling and use of chemical weapons; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHR'I R. L. BHATIA): (a) At their meeting at Rio de Janeiro on 14 June, 1992, the Prime Ministers of India and Pakistan had agree that the bilateral dialogue should be resumed. The dates for the next round of Foreign Secretary level talks were to be decided through diplomatic channels. These talks are now scheduled to be held in New Delhi from 16 to 19 August, 092.

(b) to (d) There is no fixed agenda for these talks,. They are expected to cover the entire gamut of bilateral relations.

The question was actually asked on the floor of the Huse by Shri Anant Ram Jatswal.

श्री अनन्त राम जायसवाल : उप-सभापति महोदया, सवाल के घण्टे में मैं रोज हाथ उठाता हूं, आपसे इशारा भी मिलता है, लेकिन . . .

उपसभापति : समय खत्म हो जाता है ।

श्री अनन्त राम जायसवाल : ऐन मौके पर आप निगाह फेर लेती हैं ।. . . (व्यवधान) . . .

एक माननीय सदस्य : अरे, बोलिए, सवाल पूछिए न ।

श्री अनन्त राम जायसवाल : आज मौका दिया, इसलिए आपका शुक्रिया । . . . (व्यवधान) . . .

श्री चतुरानन मिश्र : इशारेबाजी ज्यादा हाऊस में अच्छी नहीं, हाऊस के बाहर ही रखिए । . . . (व्यवधान)

श्री अनन्त राम जायसवाल : माननीया, प्रधानमंत्री जी को याद होगा कि पाकिस्तानी प्रधान मंत्री के साथ नाश्ता लेकर जब वह विदा होने के तुरंत बाद उन्होंने समाचार पत्रों व मासमीडिया के लोगों के सामने यह इच्छा जाहिर की थी, पाकिस्तानी प्रधान मंत्री ने, कि दोनों देशों में फौज पर कम खर्चा हो, फौज का खर्चा घटे । तो उनकी इस इच्छा को ध्यान में रखते हुए और उसके लिए भी जरूरी है कि दोनों देशों में आज जो तनाव है" वह खत्म हों, इस बात को ध्यान में रखते हुए और उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए भारत सरकार उनके सामने यह प्रस्ताव रखेगी कि राष्ट्रकुल के तर्ज पर, राष्ट्रकुल के आधार पर पाकिस्तान और हिन्दुस्तान का एक ढीलाढाला महासंघ बने, जिसमें भूटान भी शामिल हो, नेपाल भी शामिल हो, बर्मा चाहे तो वह भी शामिल हों, श्रीलंका भी शामिल हो ? क्या इस प्रस्ताव को रखेंगे आप ? और, यह इसलिए भी जरूरी है कि कश्मीर विवाद पर अब तक जो हमको मदद मिलती थी यू.एस.एस.आर. से, वैसी मदद देने की हालत में आज रूस नहीं है या प्रायः कोई मदद देने की हालत में नहीं है । इन चीजों को ध्यान में रखिए । तो क्या इस प्रस्ताव को, जिससे दोस्ती के रास्ते पर आयें दोनों देश, इस प्रस्ताव को रखेंगे आप इस वार्ता में ?

THE PRIME MINISTER (SHRI P. V. NARASIMHA RAO): Madam, the hon. Member is taking me by great surprise. He is producing a scheme about which I know nothing. I can only imagine, but answering the question, by imagination, would be very dangerous. I would like to have a viable proposition. I would like him to give me some details about it. We can discuss. I am open to all suggestions, useful suggestions, in the matter of improving relations with our neighbours, particularly, Pakistan, where we do have some tiffs. *I* will be happy to discuss it with ham. But first, he should give some outline so that we can discuss it.

श्री अनन्त राम जायसवाल : माननीया, यह विचार कोई नया नहीं है । इस देश की पार्लियामेंट में, प्रधानमंत्री जी पहले विदेश मंत्री भी रह चुके हैं, इस देश की पार्लियामेंट में कई दफे यह विचार आया है । उस पर चर्चा हुई है और आज जो रूस में राष्ट्रकुल बना है यू.एस.एस. आर. की जगह पर, हमने तो यह कहा है उसके आधार पर क्या भारत और पाकिस्तान का कन्फड्रेशन, ढीलाढाला ही कन्फेड्रेशन बनाने का विचार सरकार रखेगी पाकिस्तान के विदेशमंत्री के सामने ?

SHRI P. V. NARASIMHA RAO: Madam, this actually introduces another factor that I have to first study the *Rashtrakul,*—which has come now, about which not much clarity has come. The point is, if there is a proposal,—apart from the Rastrakal-which can be called a viable proposal, which could be accepted by all concerned—there ace so many hurdles to cross—and if the details are forthcoming from the hon, Member, we will certainly consider, discuss it with him. But we do not really have to go to the model of the new *Rashtrakul* because there is some sort of lack of knowledge about that than what what could perhaps improvise.

उपसभापति : डा0 अबरार अहमद ।

श्री अनन्तराम जायसवाल : मेरा दूसरा सप्लीमेंटरी ।

उपसभापति : आपका दूसरा हो गया न । ...(व्यवधान)...

SHRI S. VIDUTHALIA VTRUMBI: That was part (b) of the first supplementary.

एक माननीय सदस्य : एक और मलाऊ कर दीजिए ।

श्री अनन्तराम जायसवाल : वह पहला ही सवाल था ।

THE DEPUTY CHAR MAN: I thought you had got up twice.

श्री अनन्तराम जायसवाल : प्रधान मंत्री के जवाब की वजह से, एक ही सवाल था ।

माननीया, पाकिस्तान में जो इस वक्त आंतरिक सत्ता-संघर्ष चल रहा है, उसको देखते हुए पाकिस्तान का रुख हिन्दुस्तान के प्रति और कड़ा होगा ऐसी संभावना है और उसके आसार जाहिर भी होने लगे हैं। पाकिस्तान ने आरोप लगाया है कि सिंध के उग्रवादियों को भारत सहायता दे रहा है, यह आरोप लगाना उन्होंने शुरू कर दिया है। लेकिन दूसरी तरफ वास्तविकता यह है कि बड़ी मात्रा में पाकिस्तान हथियार दे रहा है, उग्रवादियों को ट्रेनिंग दे रहा है, उनका हिन्दुस्तान में सशस्त्र प्रवेश करा रहा है। अभी कश्मीर में और गुजरात में, दोनों जगह हथियारों के जखीरे पकड़े गये हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या इस वार्ता में भारत सरकार पाकिस्तान के सामने यह विचार रखेगी कि पाकिस्तान की यह सीधी लड़ाई है हिन्दुस्तान के खिलाफ या कम से कम हिन्दुस्तान के आंतरिक मामलों में उसका बहुत बुरा दखल है। क्योंकि इससे साम्प्रदाकिता को बल मिलता है और हमारे देश का जो ढांचा है, उसी के बिखर जाने का डर रहता है। तो क्या आप पाकिस्तानी विदेश मंत्री को सख्ती से यह बतायेंगे कि भारत इसको लड़ाई मानता है और जवाबी कार्रवाई करेगा ?

श्री आर० एल० भाटिया : पहली बात तो यह है कि हमारा कोई दखल सिंध में नहीं है, यह एक इल्जाम जिसको हम पूरी तरह से डिनाई करते हैं

श्री अनन्तराम जायसवाल : हमने यह नहीं कहा कि आपका दखल है, हमने कहा कि वह आरोप लगा रहा है।

उपसभापति : अच्छा, अभी जवाब दे दीजिए उनको ।

श्री आर० एल० भाटिया : दूसरी बात यह है कि यह जो सैक्रटरीज की कांफ्रेंस हो रही है 16 और 19 के दरम्यान पाकिस्तान और हिंदुस्तान के सैक्रटरीज के दरम्यान, यह सारे मामले उसमें विचाराधीन हैं और हिंदुस्तान ने उनके प्राइम मिनिस्टर को भी, जब प्राइम मिनिस्टर साहब मिले थे नवाज शरीफ साहब को, पूरे जोर से बता दिया था और इस मीटिंग में भी हिन्दुस्तान अपना पक्ष पूरे जोर से पेश करेगा।

डा0 अबरार अहमद : मैडम, पंजाब कश्मीर, यू०पी० के तराई क्षेत्र में पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद को बढ़ावा, आतंकवादियों को पाकिसतन के अंदर ट्रेनिंग, एक हजार से ज्यादा अफगान मुजाहिदों का विध्वंसकारी हथियारों के साथ भारत की सीमा में प्रवेश, भारत के अंदरूनी मामलों में बयानबाजी तथा भारत के विरुद्ध दुष्प्रचार ये सब बातें इस बात की प्रतीक है कि पाकिस्तान किसी भी वार्ता को गंभीरता पूर्वक लेने का इच्छुक नहीं है, बल्कि अपना जो अंतर्राष्ट्रीय पक्ष वह खो चुका है और जिसमें उसके पारंपरिक समर्थक-अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस आदि अन्य देश भी उसको यह बता चुके हैं कि भारत के अंदर जो आतंकवाद चल रहा है, वह पाकिस्तान की शह पर चल रहा है, वह किसी भी वार्ता के माध्यम से उस अंतर्राष्ट्रीय पक्ष को दोबारा चाहता है। तो मैं इस संबंध में माननीय मंत्री जी से यह

जानना चाहूंगा कि यह जो वार्ता होने वाली है, क्या इस वार्ता में कुछ मुद्दे क्योंकि तारीख बहुत नज़दीक है, तय हो चुके हैं और शिमला समझौते के अनुसार क्या हम उनको प्रैस करेंगे कि इस विवाद का हल किया जाए तथा साथ ही साथ जो विध्वंसकारी गतिविधियां भारत के विरुद्ध पाकिस्तान चला रहा है, इस संबंध में उनको चेतावनी दी जाएगी ?

इस संबंध में मैं माननीय मंत्री जी से एक बात जानना चाहता हूं कि क्या 11 जुलाई को पाकिस्तान के प्रधान मंत्री नवाज शरीफ ने ढाका में एक समाचार पत्र "डेली स्टार" को दिए गए बयान, जिसमें भारत पर मानवाधिकार के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए यह कहा गया था कि जब तक कश्मीर का विवाद रहेगा, हमारे संबंध भारत से नहीं सुधर सकते। तो क्या इसके प्रोटेस्ट के रूप में या भारत की जनता का आदर करते हुए इस वार्ता को निरस्त करेंगे अथवा यह एक राजनीतिक मामला है, इस वार्ता को सचिव स्तर से हटाकर मंत्री स्तर, विदेश मंत्री स्तर या प्रधान मंत्री स्तर पर करेंगे ? धन्यवाद ।

श्री आर० एल० भाटिया : मैडम, यह बात दुरुस्त है कि दुनिया में दूसरे देशों के लीडर्स ने भी इस बात का पूरे जोर से खंडन किया है कि पाकिस्तान कश्मीर में और पंजाब में हस्तक्षेप कर रहा है। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने भी ऐसा कहा है और अमेरिका की सीनेट में भी यह डिस्कशन हुए हैं और उनके लीडर्स ने भी यह पूरे रूप से प्रकट किया है। ई०ई०सी० कंट्रीज भी उसको ऐसा समझते हैं। बाकी जहां तक इस मीटिंग का ताल्लुक है, मैं यह बताना चाहूंगा कि बड़े जोर से हम इस बात पर डिस्कशन करेंगे, यह जो सैक्रेटरीज़ की मीटिंग है, हमारा जो दृष्टिकोण है उनको जोर से बतायेंगे और उनको हम इस बात के लिए कोशिश करेंगे, प्रेरणा देंगे कि दोनों मुल्कों का आपस में बातचीत के जरिए मसला हल करना ही ठीक तरीका है। इस तरह से इलजाम लगाना या इस तरह की बातें करने से कोई मसला तय नहीं होगा। हमारी कोशिश होगी कि हम बाई नैगोशिएशन्स, बाई टाक्स, उनसे बातचीत करके इस मसले का हल निकालें।

SHRI G. G. SWELL: Every knowledgeable person knows what is happening in Pakistan and in her vicinity. She has; played a major role in bringing about a change of guard in Afghanistan. She has moved fast on that towards close Governmental cooplerational between the two countries. Her intelligence outfits are reported to have infiltrated into the structure in Afghanistan. She has easy open access to the vast Central Asian Islamic Republics. The Afghan Mujahidins are said to be in Kashmir. They soon may be followed by Iranian volunteers. I would like to know in this context: (1) whether there has been a cerebration in extenso and in depth in the Ministry about these developments in Pakistan and in her vicinity and their relationship with Irviia; (2) whether these considerations have gone into the mind-set of Pakistan ia all her negotiations with us: and (3) whether there are instructions to our-Offi-cers that when they talk to Pakistan and negotiate with Pakistan, they keep these things at the back of their mind?

SHR'I R. L. BHATIA: It is true that all these points which the hon. Member has mentioned, will be borne in mind while talking at the Secretaries' Conference. All these matters have already been discussed also at various levels and I assure you that all these matters will be taken into consideration and India's viewpoint will be brought to the notice of the Secretaries very strongly.

SHRI INDER KUMAR GUJRAL: While T appreciate and support the initiative taken by the Prime Minister for improvement of relations and normalisation of relations with Pakistan and while the series of talks that are being held between Foreign Secretaries could possibly serve a useful purpose, I am somewhat concerned to see a latest report regarding the remarks of the Secretary-General of Foreign Affairs, Mr. Zaqi. On 28th of July he said that "the

Kashmir issue would be on the top of the agenda at the Foreign Secretary level talks between India and Pakistan to be held in Delhi next month". He preambled it. He preambled it by saying that 'the will of the nation is the last touch-stone regarding State policy and I don't think that the people of Pakistan and Kashmir are in a mood to accept any change in our policy.' May I ask the hon. Minister if any notification |has been received that they want to mqve this and this is on the top of the agenda, or is it that he is only tryng to please his own constituency in Pakistan?

SHRI P. V. NARASIMHA RAO: When we said that there will be no set agenda, it does not mean that there will be no topic to discuss. We have the topics uppermost in our mind. We have our concerns and we start with those concerns. The only thing is that unfortunately whenever there are talks slated whether between the Secretaries or between the Prime Ministers, it has almost always 'happened that something has been done from the Pakistan side at what level, I can't say; under what instructions, or no instructions, I cannot say. But the effect has been to dampen the enthusiasm with which we approach each other to discuss. Now, this is a matter which needs to be very carefully noted. If we fall a prey to that, then those who are doing it will the triumphant. We should not fall a prey to that. We are neighbours. We go on talking in spite of the setbacks. There is a very great setback. Naturally talks cannot take place in a bitter atmosphere Therefore, we put them off for some time. But this is a continuous process. Until we are able to break througli—this barrier created artificially or created naturally—I do not know which—we have to go on talking and we have to be on guard. That is the most important thing that we should be prepared. For, talks, yes, but the same time we should also be on guard. This is the policy.

श्री शांति त्यागी : मैडम, कल पाकिस्तान आकुपाईड कश्मीर के एक कस्बे में पाकिस्तान के प्रधान मंत्री जी ने ये कहा कि पाकिस्तान का परम उद्देश्य आब्जेक्टिव ये है कि हम भारत के शासन से कश्मीर को मुक्त करेंगे। ये कल ही घोषणा की है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि ऐसी एक बार लाईक घोषणा के बाद जो मीटिंग्स फारेन सेक्टरीज की हो रही है, इसमें और इससे पेश्तर क्या प्रधान मंत्री जी पाकिस्तान के प्रधान मंत्री से कहेंगे कि ऐसे वक्तब्य देना निराशाजनक है और आग जो डायलांग बातचीत का होगा, उसके लिए नुकसानदेह है।

श्री आर० एल० भाटिया : पांच तारीख को रावलकोट के मुकाम पर नवाज शरीफ ने ये स्टटमेंट दी थी कि——

that Pakistan had a mission to liberate Kashmir.

आगे भी यह बात, प्रधान मंत्री जी की चार मीटिंग्स हो चुकी है नवाब शरीफ के साथ मुख्तलिफ जगहों पर और ये बात को इम्फैसाइज़ किया गया था कि कोई भी ऐसे बयान न दिए जायें जो कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को खराब करें। अब जो बयान उन्होंने दिया है उसका तो जवाब यही है कि——

Kashmir is an itegral part of India and there can be no compromise on India's unity and integrity.

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : श्रीमन्, मेरे सहयोगी अबरार साहब ने सवाल किया था, मैं उसको दोहराता हूं, उसका जवाब नहीं दिया गया। उससे पहले मैं पूछना चाहूंगा कि जब बार-बार हमारी बातचीत होती है उसमें से नतीजा कुछ नहीं निकलता और पिछल 15–20 दिन में तो सीमाओं पर आक्रमण एक प्रकार से किए जा रहे हैं। तो ऐसी पृष्ठभूमि में सरकार इसमें से क्या निर्णय निकालना चाहती है और क्या सरकार अपनी सख्ती का रवैया प्रकट करने के लिए इस वार्ता को नकार न दें, मंत्री महोदय बतायें तिथियां, वह शायद पहले तय हुई थीं लेकिन अब जो हालात हुए हैं, उस बदली हुई स्थिति में मेरा आग्रह यह है शायद आप मानें या न मानें कि ये वार्ता तोड़ देनी चाहिए, समाप्त कर देनी चाहिए अपनी नाराजगी

कट करने के लिए . . . (**व्यवधान**) उसी का इस्सा है, उसी का हिस्सा है . . . (**व्यवधान**)।

श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम श्रफजल : सवाल है ये आपका . . . (**व्यवधान**)

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : नहीं-नहीं, सवाल भी है कि क्या आप तोड़ेंगे . . . (**व्यवधान**) सवाल है, मैंने कहा है कि क्या आप तोड़गे . . . (**व्यवधान**)

श्री मोहम्मद श्रफजल उर्फ मीम श्रफजल : बातचीत तोड़ दीजिए, सवाल कहां है . . . (**व्यवधान**)

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : नहीं, मैंने कहा है कि क्या आप तोड़ेंगे . . (**व्यवधान**)

उपसभापति : अभी आप बैठिए, उनको कहने दीजिए . . . (**व्यवधान**) प्लीज मिस्टर अफजल, प्लीज . . . (**व्यवधान**) बैठिए . . . (**व्यवधान**) माथुर साहब, आप तो इधर सवाल करिए . . . (**व्यवधान**)

श्री जगदीश प्रसाद माथुर: इनको तो रोकिए।

उपसभापति : मैंने रोका है . . . (**व्यवधान**)

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : क्या आप इस वार्ता को पोस्टपोन करेंगे ? एजेंडा में आपने कहा कुछ भी नहीं है, मैं वैसे ही पूछता हूं कुछ दिनों पूर्व पाकिस्तान ने यह सुझाव दिया था कि जेनेवा कन्वैंशन के अलावा एक स्पेशल हमारी ट्रीटी हो जो हमारी डिप्लोमेट्स के आचरण के विषय में हो। क्या ये बात भी आप उनके सामने दोबारा विचार कर रहे हैं या रद्द कर रहे है ?

श्री आर०एल० भाटिया : पहली बात तो यह है कि हमारी पोलिसी पाकिस्तान से बातचीत करके जोड़ने की है, तोड़ने की नहीं है। क्योंकि मीटिंग्स में कोई न कोई बात निकलती है, कोई न कोई फैसले होते हैं।

श्री अजीत जोगी : यह तोड़ने की बात करते हैं।

श्री आर० एल० भाटिया : जैसे कि पिछली मीटिंग्स में हम दो फैसले कर पाये। एक तो यह कि दोनों मुल्क के दरम्यान जब हम मिलट्री एक्सरसाईजेज करें तो एक दूसरे को पहले चेतावनी दें और दूसरा यह फैसला किया था कि जो हमारे मिलट्री के जहाज है, एक दूसरे की एयर स्पेस में न जायें। तो बातचीत से कुछ न कुछ निकलता है। अब भी जो मीटिंग होगी इसमें भी वह तमाम मुद्दे जिनका आप चिंतन कर रहे हैं या देश में लोग महसूस करते हैं, वह सारी बातें हम वहां रखेंगे और हमें उम्मीद है कि उसका कोई न कोई फैसला जरूर होगा जहां तक आपने यह बात कही . . . (**व्यवधान**)।

श्री प्रमोद महाजन : एक दूसरे के एयर स्पेस में न जायें, यह कोई फैसला होता है।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : यह आप उसका अचीवमेंट कह रहे हैं। यह तो अंडरस्टेंडिंग है क्योंकि जब कभी ऐसी फौजी एक्सरसाइजेज होती हैं, बताया जाता है। यह तो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति है।

श्री आर० एल० भाटिया : माथुर साहब, आप मुझे मौका देंगे, मैं आपकी ही बात का जवाब देता हूं। आपने कहा कि यह कोई फैसले होते हैं। यह जो फैसले होते हैं यह एक-एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेसर्स होता है दो देशों में इसीलिए यह फैसल किए जाते हैं। दूसरी बात है, आपने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से एक कोड जो डिप्लोमेट की तरफ है, वह हमको प्राप्त हो चुका है। हमने उसमें कुछ अमेंडमेंट करके उनको ड्राफ्ट भेजा है और उसमें जो उन्होंने हमको प्रपोज किया, हमने उनकी सारी बातें नहीं मानी। उसमें एड किया है कि कैसे डिप्लोमेट की सेफ्टी दोनों कंट्री में होनी चाहिए। उसका जवाब बाकी है और जब वह जवाब आएगा तो हाउस को बता दिया जाएगा।

श्री चतुरानन मिश्र उपसभापति : महोदया, पाकिस्तान और भारत के बीच जो बातचीत होती है उसमें एक सवाल जो उठता है कि साउथ एशिया को

न्यूक्लिअर फ्री जोन बनाया जाए। यह बात पिछले वर्षों के अंदर बहस में कई बार आई है। इस पर दुनिया में जो हमारी अभी स्टेंड है, उसमें हम लोगों को साथ नहीं कर पाते हैं। भारत ही ऐसा देश है जिसने शांति के लिए अपनी आजादी की प्राप्ति के बाद और सरकार बनने के बाद और उसके पहले भी गांधी जी ने इसकी बड़ी चर्चा की। लेकिन आज इस सवाल पर और खासकर के जब एन०पी०टी० पर दस्तखत करने की बात थी, तो हमारे प्रधान मंत्री जी ने कहा कि अभी उसको रिव्यू करने का मौका आया है, क्योंकि 1995 में वह समाप्त हो रहा है। तो अब यह नई घटना घटी। फ्रांस ने उस पर फिर दस्तखत डाल दिया। तो हम जानना चाहेंगे कि नान-प्रोलिफिरेशन ट्रीटी के बारे में जो रिव्यू करने का था ...(व्यवधान) अपना सेन्टेंस खत्म करूंगा, तभी क्लीअर होगा। ...(व्यवधान) हम यह कहना चाहते हैं कि उसको देखते हुए क्या इंडिया कोई फ्रेश इनीसिएटिव लेगा? क्योंकि वर्ल्ड पब्लिक आपिनियन इस तरह का बन रहा है और यहां हमको न्यूक्लिअर फ्री जोन बनाने के सवाल पर कोर्नर कर रहे है और दुनियां के दूसरे राष्ट्र भी उस पर हमारी नीति को पसंद नहीं कर रहे हैं। तो इंडिया इस संबंध में कोई फ्रेश इनीसिएटिव लेगा? इस और हमारी सरकारी सोच रही है या नहीं?

श्री आर० एल० भाटिया : सवाल के साथ यह जुड़ता तो नहीं है, लेकिन अगर आप कहती हैं तो मैं उनको बताए देता हूं।

श्री चतुरानन मिश्र : मैं अपनी बात स्पष्ट कर दूं।

उपसभापति : आपने इतनी देर में तो स्पष्ट की नहीं, अब क्या करेंगे? ...(व्यवधान) पी०एम० साहब जवाब दे रहे हैं।

SHRI P. V. NARASIMHA RAO: This cannot be a subject for Secretary-level talks. This is something very different. If you want, on some occasion, I am prepared to go into it in g detail and explain the stand of the vermment. This (has been appireti; throughout although we are under p sure. We have been under pressure a since the Treaty began. Now the The has only a few years and perhaps, i going to be reviewed. So, the press will, perhaps, mount. But I cc make a statement or I could explain position on some other occasion not connection with this question.

उपसभापति : क्वेश्चन नं० 423।

डा० अबरार अहमद : मैडम, इस प हाफ-एन-आवर डिस्कशन बहुत महत्वपू है।...(व्यवधान)

उपसभापति : क्वेश्चन नं० 42 चतुरानन जी, प्लीज, प्रधान मंत्री जी ने क दिया कि...(व्यवधान)

श्री चतुरानन मिश्र : न्यूक्लियर फ्री जो बनाने के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा ...(व्यवधान)

उपसभापति : प्रधान मंत्री जी के आश्वास के बाद कि वह इस मामले पर लम्बी बह और विचार-विमर्श के लिए तैयार हैं। मु लगता है कि क्वेश्चन-423 पर जाएं त ज्यादा अच्छा रहेगा।

डा० अबरार अहमद : मैडम, यह महत्व पूर्ण विषय है और राष्ट्रीय हित का है एक सप्लीमेंट्री में बहुत सीमित बात पूछी ज सकती है। प्लीज, आधे घंटे की इस पर चच करा दें।

उपसभापति : किस पर?

डा० अबरार अहमद : क्वेश्चन-422 पर, जो अभी समाप्त हुआ है।

उपसभापति : किस पर?

डा० अबरार अहमद : 422 पर यह बड़ा इम्पोर्टेन्ट सवाल है।

THE DEPUTY CHAIRMAN: A right. The Members can write to us ar we will take a decision on it. But junew, let us go ahead with the other question.